# भवन नक्शा कंप्लीशन में करोड़ों का खेल

## हरामखोरी और रिश्वतखोरी का जीता जागता प्रमाण है नगर निगम

**फ़रीदाबाद ( मज़दूर मोर्चा )** नगर निगम को कंगाल बनाने वाले अधिकारी अब भवन कंप्लीशन घोटाले का खेल खेल कर इसे लूटने में लगे हुए हैं। निगम के अधिकारी, दलाल आर्किटेक्ट और ठेकेदार गठजोड़ बना कर नियम ताक पर रखकर बनाए जा रहे भवनों का कंप्लीशन करा रहे हैं। कंप्लीशन से मिलने वाला जो धन निगम के खाते में जाना चाहिए था वह भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है। यही कारण है कि निगम लगातार धन की कमी से जूझ रहा है जबकि इसके अधिकारी मालामाल होते जा रहे हैं।

फरीदाबाद नगर निगम के सभी जोनों में भवन निर्माण के नियम ताक पर रख कर जगह-जगह धड़ल्ले से इमारतें बनाई जा रही हैं। रिहयाशी नक्शा पास कराकर उसमें कमर्शियल निर्माण कराए जा रहे हैं। बिल्डिंग बाईलॉज के उल्लंघन के साथ फ्लोर एरिया रेश्यो की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

शहर में ऐसी अनेक इमारतों का निर्माण बेखौफ जारी है जिनमें सौ प्रतिशत एरिया कवर्ड कर दिया गया है। इसके बावजूद सड़क पर छज्जे भी निकाले गए हैं। सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल भवन निर्माण पर अस्थायी रोक लगा रखी है उसके बावजूद नगर निगम क्षेत्र में स्टिल्ट के नाम पर दस से बारह फीट पर लेंटर डाल कर चार मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। इनमें स्टिल्ट पार्किंग की जगहों का इस्तेमाल कमर्शियल गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अनेक जगहों पर स्टिल्ट के साथ चार मंजिल नक्शे पास किए गए और उनमें टुकड़ों में डबल यूनिट फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ऐसे निर्माणों को जिनमें अतिरिक्त निर्माण किया हुआ है कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिलवाने में कई दलाल व आर्किटेक्ट निगम में सक्रिय हैं। कुछ आर्किटेक्ट व दलाल रिहायशी इलाकों में ऑनलाइन रिहायशी नक्शे पास करवा कर उसमें कमर्शियल निर्माण भी करवा रहे हैं।

कंप्लीशन के इस खेल में अपना दामन साफ रहे इसके लिए कमिश्नर ने कौशल रोजगार (ठेके) के जूनियर इंजीनियरों को कमान दे रखी है। सैनिक कॉलोनी, एनआईटी एक, दो, तीन और पांच सहित अन्य जगहों पर जमकर भवन निर्माण और कंप्लीशन का खेल जारी है। निगम के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार शहर में जो भी भवन बन रहे हैं उनमें से ६५ प्रतिशत भवनों में नक्शा, कंप्लीशन, सबडिवीजन फीस, सीएलयू फीस नहीं जमा कराई जा रही है। जो कंपाउंडेबल फीस सरकारी खजाने में आनी चाहिए वह रिश्वतखोरी के जरिए अधिकारियों की जेब में पहुंच रही है। अधिकारी शहर की सुंदरता को बट्टा लगाकर अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं।

### खुफिया विभाग की रिपोर्ट भी बेकार

शहर में अवैध निर्माण की गूंज से सक्रिय हुए खुफिया विभाग ने जमकर रिपोर्टें बनाईं और मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के साथ कई जगह छापे भी डाले। एनआईटी तीन में तो एक सील अवैध निर्माणाधीन भवन में ही काम चलते हुए मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने पकड़ा और कागज कब्जे में लिए। लेकिन अब रिपोर्ट के नाम पर चुप्पी साध ली। कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर घिसा पिटा जवाब मिलता है कि सरकार को कार्रवाई के लिए भेज रखा है। सवाल यह है कि करोड़ों के राजस्व घोटाले में सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती या सरकार के पास कोई रिपोर्ट पहुंचती ही नहीं। राज्य चौकसी ब्यूरो के पास अवैध निर्माण संबंधी अनेक जांच पड़ी हैं जिनका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

---

**रिवाज़पुर डंपिंग यार्ड**

# नस्लें और फसलें बर्बाद करने पर उतारू चाटुकार अधिकारी

## मंत्री की मंशा के आगे जनता का हित नहीं देख रहा शासन-प्रशासन

**फ़रीदाबाद ( मज़दूर मोर्चा )** सत्ता के चाटुकार नगर निगम अधिकारियों के लिए जनता का हित और पर्यावरण संरक्षण जैसी बातें मायने नहीं रखतीं। यही कारण है कि कोई शोध, सर्वे कराए बगैर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्तिपत्र हासिल किए बिना ही रिवाज़पुर जैसी ज़रखेज़ और उपजाऊ जमीन पर डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला ले लिया गया। करीब साठ हजार की आबादी के बीच में यदि यह डंपिंग यार्ड बनकर तैयार हुआ तो भविष्य की नस्लों और फसलों को इसका दुष्प्रभाव झेलना होगा।

रिवाज़पुर गांव में डंपिंग यार्ड बनाए जाने का विरोध कर रही रिवाज़पुर सोशल वेलफेयर संघर्ष समिति के सदस्य नाहर सिंह कहते हैं कि बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड में खड़े

कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए सरकार ने फरीदाबाद की छह विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डंपिंग यार्ड बनाने की घोषणा की थी। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में मुजैड़ी गांव में एक डंपिंग यार्ड बन रहा है तो दूसरा रिवाज़पुर में नहीं बनना चाहिए।

सदस्य रवींद्र चावला ने कहा कि निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने डंपिंग यार्ड बनाए जाने से पहले इलाके का सर्वे कराने की भी जहमत नहीं उठाई। खेतों और उपजाऊ जमीन पर डंपिग यार्ड बनाने का टेंडर जारी कर दिया गया। डंपिंग यार्ड आबादी से दूर किसी अनुपजाऊ या बंजर जमीन पर बनाया जाना चाहिए। फरीदाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, बावजूद इसके नगर निगम ने डंपिंग यार्ड बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया।

सदस्य माला चौहान बताती हैं कि डंपिंग यार्ड से यमुना नदी की दूरी एक किलोमीटर से भी कम है और इसी इलाके में शहर को पानी सप्लाई करने वाली रैनीवेल लाइनें पड़ी हैं। यार्ड में पड़े कूड़े के सड़ने से निकली गंदगी रिस कर भूगर्भ जल को दूषित करेगी, यही पानी रैनीवेल के जरिए शहर को सप्लाई किया जाएगा। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैलने का खतरा है।

आरोप लगा कि रिवाज़पुर में डंपिंग यार्ड केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर की इच्छा पर बन रहा है, उनका कहना है कि मैने कह दिया कि डंपिंग यार्ड बनेगा तो बनेगा। शायद रिवाज़पुर को विरोध के बावजूद नगर निगम क्षेत्राधिकार में इसीलिए शामिल कराया गया कि यहां मंत्री की इच्छा पर डंपिंग यार्ड बनाया जा सके।

कुसुम भाटी कहती हैं कि कृष्णपाल गूर्जर को रिकॉर्ड मतों से जिताने का यही नतीजा है कि सोलह गांवों को कोई अच्छा स्कूल, पार्क, अस्पताल देने के बजाय बीमारी और प्रदूषण का केंद्र डंपिंग यार्ड दिया जा रहा है। डंपिंग यार्ड बनाए जाने का फैसला वापस लिए जाने तक संघर्ष समिति के सदस्य आमरण अनशन पर बैठेंगे।

डंपिंग यार्ड बनाए जाने का खिलाफ जनता का यह विरोध न तो पहला है और न आखिरी। करीब दो साल पहले सीही में भी डंपिंग यार्ड बनाने का तुगलकी फरमान जारी हुआ था। लोगों के भारी संघर्षपूर्ण विरोध पर निगम अधिकारी पीछे हट गए और फिर बिना किसी तैयारी के पाली गांव में डंपिंग यार्ड की घोषणा कर दी। यहां भी कड़ा विरोध झेलना पड़ा तो सोतई गांव चुना गया। अब रिवाज़पुर गांव की उपजाऊ जमीन और आबादी के बीच डंपिंग यार्ड बनाए जाने का अवैज्ञानिक निर्णय लिया गया है।

लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में नए गांवों को विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि डंपिंग यार्ड बनाए जाने के लिए ही शामिल किया जाता है। पलवल नगर पालिका परिषद में फिरोजपुर गांव को जोड़ा ही इसलिए गया कि वहां स्कूल, अस्पताल के बजाय कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा सके। दरअसल, नगर निगम के नाकारा और चाटुकार अधिकारी किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अध्ययन तो करते नहीं, बल्कि जो उनके राजनीतिक आका कह देते हैं उसको बजा लाने में जुट जाते हैं। ऐसे में जनता का विरोध स्वाभाविक है।

### शासन प्रशासन प्रशासन के निकम्मे व चोर अधिकारियों ने ठीक से काम किया होता तो आज यह नौबत न आती

यदि पाठक भूले न होंगे जब बंधवाड़ी का डंपिंग यार्ड बनाया गया था तब इन चोर अधिकारियों ने लंबी लंबी छोड़ते हुए कहा था कि अब यहां कूड़े से बिजली बनेगी, घर घर बिजली मिलेगी, खेतों के लिए खाद मिलेगी। करदाता के सैकड़ों करोड़ रुपयों को पलीता लगाने के बाद आज न तो कहीं गैस बनती दिख रही है न खाद। ऐसा नहीं है कि इस कूड़े से सब चीजें न बनती हों, आज तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी है कि कूड़े से यह सब चीजें बन रही हैं लेकिन वहां के न तो नेता चोर हैं और न ही अधिकारी, लेकिन यहां तो सारे बावन हाथ के हैं। अगर ठीक से काम हुआ होता तो आज न तो इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ होता न जनता त्राहि, त्राहि कर रही होती और इससे बिजली, गैस व खाद बन रही होती। और तो यह क्या करते इनसे आज तक सही से कूड़े की छटाई तक नहीं हो पाई। केवल 21 प्रतिशत कचरे की ही छटाई होती है बाकी पहाड़ की ऊंचाई बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बंधवाड़ी के बाद वही कारस्तानी दोहराने के लिए जगह जगह टक्कर मारते फिर रहे हैं लेकिन जनता विरोध कर रही है और लट्ठ लेकर खड़ी है।

---

### बादशाह खान अस्पताल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का रैकेट सक्रिय

**फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)** बादशाह खान अस्पताल से निकाला गया पूर्व संविदाकर्मी यहां फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हुए पकड़ा गया। खास बात यह रही कि अस्पताल कर्मियों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले करने के बजाय जाने दिया। मामला मीडिया में आने के बाद पीएमओ ने अपना दामन बचाने के लिए पुलिस को शिकायत देकर पल्ला झाड़ लिया।

अमरनाथ यात्रियों का मेडिकल सर्टिफिकेट बादशाह खान अस्पताल में बनाया जा रहा है। इसके तहत अस्पताल से मिलने वाला निशुल्क फार्म भर कर आवेदक अस्पताल में जमा करवाता है। जांच होने के बाद इसी फार्म पर मेडिकल फिटनेस सत्यापित की जाती है। इसके बाद इस फार्म पर आरएमओ और पीएमओ के हस्ताक्षर होते हैं। अंत में इस फार्म पर एक नंबर दिया जाता है जिसके आधार पर अमरनाथ तीर्थ यात्री बैंक में फीस जमा करवाते हैं।

मंगलवार को अस्पताल का एक पूर्व संविदाकर्मी जिसका नाम राजेंद्र बताया जा रहा है अपने एक साथी हिमांशु के साथ सैनिक कॉलोनी निवासी बुजुर्ग विजय अरोड़ा का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर उसमें नंबर चढ़वाने पहुंचा। राजेंद्र ने बुजुर्ग का मेडिकल कराए बिना ही फार्म पर फिटनेस सत्यापित की। यही नहीं उसने फार्म पर आरएमओ, पीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर भी बनाए और पीएमओ की नकली मुहर भी लगाई थी। जांच कर रहे कर्मचारी ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ लिया। उसने पूर्व संविदाकर्मी को रोक कर उससे फर्जी फार्म के बारे में पूछताछ शुरू की। इस पर राजेंद्र और हिमांशु ने विजय अरोड़ा को बुलाने का बहाना बनाया और फोन करने के बहाने वहां से खिसक लिए। फर्जी दस्तावेज साबित होने के बावजूद कर्मचारी ने राजेंद्र और हिमांशु को पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि उन्हें जाने दिया।

कर्मचारी ने आरएमओ को फर्जीवाड़े की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पूर्व संविदाकर्मी राजेंद्र की पत्नी अस्पताल में संविदाकर्मी है और वर्तमान में प्रसूति विभाग में तैनात है। कहने को तो यह महिला संविदाकर्मी है लेकिन बताया जाता है कि महिला अस्पताल में उसकी मर्जी से ही नर्सों की तैनाती, ड्यूटी, शिफ्ट और छुट्टी तय होती है।

हालांकि इस संबंध में पीएमओ सविता यादव के आदेश पर आरएमओ डॉ. रोहित गौड़ ने पुलिस को तहरीर दी है। तीन नंबर चौकी इंचार्ज ने बताया कि शिकायत मिली है जांच की जा रही है, गड़बड़ी पाए जाने पर केस दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस सारे फर्जीवाड़े में कौन-कौन शामिल हैं इस पर मज़दूर मोर्चा की तहकीकात अभी जारी है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।